

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आरोप : यूपीए सरकार ने 8 लाख करोड़ की टैक्स छूट देकर गरीबों को लूटा

Publisher

Published on 26 Sep 2025



भारतीय राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि वर्ष 2004 में यूपीए सरकार ने बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को 8 लाख करोड़ रुपये की टैक्स छूट दी थी, जिससे गरीब और आम जनता को नुकसान हुआ।

आरोप का विवरण

निशिकांत दुबे ने कहा कि यूपीए सरकार ने उस समय अपने राजनीतिक फायदे और कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए टैक्स छूट दी थी। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने आम जनता की गाढ़ी कमाई का शोषण किया और गरीबों के हिस्से का धन बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में खर्च किया।

उन्होंने ट्वीट और मीडिया बयानों के जरिए कहा:

“यूपीए सरकार का असली चेहरा सामने लाना जरूरी है। 2004 में 8 लाख करोड़ की टैक्स छूट दी गई, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के नाम पर राजनीति की, लेकिन असल में उनकी नीतियां पूंजीपतियों के पक्ष में रहीं।”

2004 का संदर्भ

वर्ष 2004 में यूपीए की सरकार केंद्र में बनी थी। यह वह दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन साथ ही बेरोजगारी, गरीबी और किसानों की समस्याएँ भी गहराई से मौजूद थीं।

- आरोप है कि इस दौरान सरकार ने कुछ विशेष उद्योगों और कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स छूट देकर उनका फायदा कराया ।
- इस टैक्स छूट की राशि लगभग 8 लाख करोड़ बताई जा रही है, जिसे बीजेपी सांसद आम जनता के साथ “विश्वासघात” करार दे रहे हैं ।

कांग्रेस की नीतियों पर सवाल

बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस हमेशा गरीबों और किसानों के हितैषी होने का दावा करती रही, लेकिन असल में उनकी नीतियां धनाढ्य वर्ग और बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली थीं ।

- निशिकांत दुबे ने कहा कि यह छूट अगर गरीबों और किसानों पर खर्च होती तो आज उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलता ।
- उनका कहना है कि कांग्रेस ने आर्थिक संसाधनों का गलत उपयोग किया और यह साबित करता है कि उनकी सरकार गरीब विरोधी थी ।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं दिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है ।

- कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ऐसे आरोप केवल राजनीतिक लाभ लेने और आगामी चुनावों में माहौल बनाने के लिए लगाए जा रहे हैं ।
- वहीं, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर जनता के सामने जवाब देना होगा ।

यूपीए सरकार और टैक्स नीतियाँ

विशेषज्ञ मानते हैं कि टैक्स छूट किसी भी सरकार की नीतियों का हिस्सा होती है । इसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना, उद्योगों को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास को गति देना होता है । लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा सामने आने के बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या वास्तव में इतनी बड़ी राशि गरीबों और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर खर्च की जा सकती थी ।

आर्थिक और सामाजिक असर

यदि निशिकांत दुबे के आरोप सही माने जाएं, तो 8 लाख करोड़ रुपये की यह छूट गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं में खर्च हो सकती थी ।

- इस राशि से करोड़ों युवाओं को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते थे ।
- किसानों को कर्जमुक्त किया जा सकता था ।
- स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार किए जा सकते थे ।

बीजेपी का आक्रामक रुख

बीजेपी ने इसे केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक न्याय का प्रश्न बताया है । निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के नाम पर वोट तो मांगे लेकिन उनके हिस्से का धन बड़े घरानों में बांट दिया । उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस इस मामले पर स्पष्टीकरण दे और जनता से माफी मांगे ।

क्या है आगे का रास्ता ?

यह आरोप आने वाले समय में संसद और राजनीतिक मंचों पर गरमा सकते हैं । बीजेपी इस मुद्दे को आगामी चुनावों में कांग्रेस के

खिलाफ बड़ा हथियार बना सकती है। दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए यह जरूरी होगा कि वह इस मुद्दे पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

निशिकांत दुबे का यह आरोप कांग्रेस के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। **8 लाख करोड़ की टैक्स छूट** का मुद्दा न केवल आर्थिक रूप से भारी-भरकम है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है।

अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह कांग्रेस की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, वहीं यदि यह सिर्फ राजनीतिक प्रचार साबित होता है तो बीजेपी की रणनीति पर भी सवाल उठ सकते हैं।

कुल मिलाकर, यह विवाद आने वाले समय में भारतीय राजनीति के बड़े बहस का हिस्सा बनने वाला है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.